an>

Title: Regarding failure of the Government to address agrarian distress leading to alarming increase in farmer suicide.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, यह सर्वविदित है कि जब तक हमारे देश का अन्नदाता सुखी नहीं होगा, तब तक देश सुखी नहीं हो पाएगा। यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में 71 हजार करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना लाई थी। इससे साढ़े तीन करोड़ किसानों को राहत मिली थी और साथ ही साथ समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की थी।

महोदया, आज की सरकार कहती है कि 'सबका साथ सबका विकास', लेकिन किसान आज आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि कर्ज़ में किसान डूब चुका है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में किसान की जो पीड़ा है, किसान पर जो भीषण संकट है, उसके समाधान के लिए किसान कराह रहा है। सरकार द्वारा किसानों की पूरी अनदेखी की जा रही है। आप तमिलनाडु के किसानों की दुर्दशा देखिए। तमिलनाडु भीषण सूखे के दौर से गुजर रहा है। वहां 62 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। दिल्ली में तमिलनाडु के किसान मृत शरीर के सिर को लेकर धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इन्होंने 40 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन सरकार दो हजार करोड़ रुपये भी नहीं दे पाई है।

महोदया, उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिखा था कि ऋण माफी योजना शुरू की जाएगी और दो करोड़ किसानों को ऋण से राहत दी जाएगी, लेकिन आज भी सरकार सिर्फ जुमले पर अटकी है और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में पन्द्रह हजार किसानों ने आत्महत्या की है।...(व्यवधान) वहां किसान संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है, आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। हम मांग करते हैं कि ऋण माफी योजना जल्द लागू की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री जी नया भारत और नये साल की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए ऋण माफी की योजना कब लागू की जाएगी?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

â€¦(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, एससी और एसटी आयोग के गठन पर माननीय मंत्री जी जवाब दिया है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने समय में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा।...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह सदन में उपस्थित हैं, वे माननीय सदस्य की बात का उत्तर देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाएं। कृषि मंत्री जी आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग मुझे पोस्टर न दिखाएं, मंत्री जी जो कहने जा रहे हैं, उसे आप सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दिन भर कागज दिखाते रहोगे, सदन में ऐसा करना अच्छी बात नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, पिछले दिनों कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान अधिकतर माननीय सदस्य मौजूद थे और मैंने अपनी बातें सदन में रखी थीं। आज तमिलनाडु या देश में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई सदन में इधर से या उधर से बैठे-बैठे कमेंट करे, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने कहा कि तमिलनाडु एवं देश और महाराष्ट्र हमारे देश का ही हिस्सा है। माननीय सदस्य ने तमिलनाडु और देश के किसानों की प्रमुखता से चर्चा की है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य आपदा कोष के अंतर्गत राज्यों के पास पैसा होता है। मोदी सरकार से पहले राज्य आपदा कोष में पांच वर्ष के लिए पूरे देश का आबंटन 24 हजार करोड़ रुपये का था। मोदी सरकार ने इस राशि को बढ़ा कर 47 हजार करोड़ रुपए किया, यह राशि अपने में रिकार्ड है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनकी बात का उत्तर सदन में नहीं दिया जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : ठीक है, महोदया।

तमिलनाडु को पांच वर्षों में राष्ट्रीय आपदा कोष में 1083 करोड़ रुपए की राशि दी गई और मोदी सरकार के आने के बाद पांच वर्षों के लिए इस राशि को बढ़ाकर तीन हजार करोड़ रुपए किया गया। जैसा मैंने बताया कि पूरे देश के लिए पांच वर्षों का आबंटन 24 हजार करोड़ रुपए का था और उसे बढ़ाकर 47 हजार करोड़ रुपए किया, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में आबंटन बढ़ाया गया। इसके बाद यदि आपदाएं ज्यादा होती हैं, तो राज्य सरकार की ओर से मांग आती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में राष्ट्रीय आपदा कोष से राज्यों को बारह हजार करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन उनकी मांग 92 हजार करोड़ रुपये की थी। मैं चार साल की बात बता रहा हूं। यदि केवल वर्ष 2014-15 की बात करूं, तो राष्ट्रीय आपदा कोष में नौ हजार करोड़ रुपये दिए गए। चार वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपए और एक वर्ष 2015 में नौ हजार करोड़ रुपये और 2015-16 में 15 हजार करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा कोष से दिए गए।वर्ष 2016-17 में हमारे पास राज्यों से जो डिमांड आई हैं, उनमें आध्र प्रदेश को 518 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 1748 करोड़ रुपये की स्वीकृति एनडीआरएफ से हुई है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार के बारे में भी बता दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप लोग फिर वही कर रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : उसके बारे में डिटेल हम आपको दे देंगे।

जहाँ तक मांग के मुताबिक तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु ने वर्ष 2012-13 में 19 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से उसे छः सौ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस बार हमने उसे 1700 करोड़ रुपये दिये हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी सहायता राशि है। वहाँ के जो किसान धरना पर बैठे हैं, वहाँ के माननीय मंत्री श्री राधाकृष्णन जी के साथ एक बार मिल चुका हूँ और सम्माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ भी मैं वहाँ के किसानों के साथ मिल चुका हूँ।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): एक बार मैं भी मिला हूँ।

श्री राधा मोहन सिंह : हमारे वित्त मंत्री जी मिले हैं, उमा भारती जी मिली हैं, निर्मला सीतारमन जी मिली हैं। ...(व्यवधान) जहाँ तक कर्ज माफी का सवाल है, ...(व्यवधान) राजनाथ जी मिले हैं, ...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ भारत सरकार की पूरी सहानुभूति और समर्थन है और हम सहायता भी कर रहे हैं।

जहाँ तक कर्ज माफी का सवाल है, आपके ध्यान में होगा कि पहले किसान ऋण लेते थे, तो नौ प्रतिशत ब्याज देते थे। जब आदरणीय राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, तो उस समय ब्याज-दर में दो प्रतिशत की कमी की गयी और राज-खज़ाने से राशि दिया जाने लगा। फिर बाद तीन प्रतिशत और राज-खज़ाने से राशि गयी। किसान मात्र चार प्रतिशत ब्याज-दर का भुगतान करते हैं। लेकिन कई राज्य सरकारों ने अपने राज-खज़ाने से, मध्य प्रदेश की सरकार ने, ...(व्यवधान) कर्नाटक में आपकी सरकार भी है, वह भी अपने राज-खज़ाने से राशि देती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात भी देती है और अब महाराष्ट्र ने भी अपने राज-खज़ाने से तीन प्रतिशत ब्याज-दर देना शुरू किया है। ...(व्यवधान) एक प्रतिशत ब्याज-दर किसान को देना पड़ता है।

आपके ध्यान में यह भी होगा कि 14वें वित्त आयोग ने कितनी राशि बढ़ायी है, इसके आँकड़े भी मेरे पास हैं। मेरे पास पूरे देश के आँकड़े हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मंत्री जी, वह केवल सहकारिता बैंकों के आँकड़े हैं। आप बाकी बैंकों के ऋण की बात कीजिए, क्योंकि 80 प्रतिशत किसान अन्य बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : कोई भी किसान, चाहे सहकारिता बैंक से ऋण लेता हो, चाहे किसी भी बैंक से ऋण लेता हो, उसको पाँच प्रतिशत सहायता भारत सरकार के खज़ाने से और चार प्रतिशत किसान किसान देता था। कई राज्य सरकारों ने अपने खज़ाने से सहायता देना शुरू किया है। वित्त आयोग ने राज्यों के लिए जो राशि बढ़ायी है, उसके बाद कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उस दिन माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी, तो हम लघु-सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे खुशी होगी कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज-खज़ाने से सहायता करेगी, चूंकि 14वें वित्त आयोग में राज्यों की राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है, यदि राज्य सरकारें सहायता करती हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। भारत सरकार न केवल किसानों के साथ खड़ी है, बल्कि कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गयी है। उनके परिणाम सामने आएंगे।

जहाँ तक आपने कर्ज माफी की बात कही, तो आपने वर्ष 2008 में कर्ज माफ किया। वर्ष 2005 में देश में जो कुल आत्महत्याएं हुई, उनमें 15 प्रतिशत किसान और कृषि कार्य से संबंधित काम करने वाले थे। वर्ष 2008 में जितनी आत्महत्याएं हुई, उनमें 13 प्रतिशत किसान और कृषिकर्मी-मजदूर थे। जब आपने कर्ज माफ किया, उसके बाद वर्ष 2009 में इसके आँकड़े 13.7 प्रतिशत हो गये। आज की तारीख में यह घटकर 9.4 प्रतिशत हुआ है।

मेरा आग्रह है कि सरकार ने जितनी योजनाएं चलायी है, मेरे पास तमिलनाडु के आँकड़े हैं, वहाँ माइक्रो-इरिगेशन के लिए पैसे गये। जब राशि दी गयी, तो वर्ष 2014-15 में नौ करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए, वर्ष 2015-16 में 22 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए, वर्ष 2016-17 में अभी तक 51 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं।

किसानों की मजबूती के लिए राज्यों में जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उस पर राशि खर्च नहीं हो रही है। 31 मार्च के बाद मैं इस विषय को भी लाऊँगा। मेरा कहना है कि हम सब लोग मिलकर किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें, ताकि किसानों की हालत सुधरे। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग और एस.सी. एस.टी. आयोग के गठन ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : एक मिनट भाई। एक मिनट आप बैठिए।

माननीय अध्यक्ष ः खड़गे जी, क्या कर रहे हैं? जयप्रकाश जी आप बोलिए। आप अभी आए हैं। इस बात पर विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है। बार-बार एक ही बात मत बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं बार-बार नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अभी आया हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष ः आप अभी आए हैं, पर आपकी पार्टी बोल चुकी है। आप अभी आए, इसलिए आपको यह बात मालूम नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष ः आप भी बोल रहे हैं, वे भी बोल रहे हैं। कौन-कौन बोलेगा। आप बैठिए। ऐसा नहीं होता है, आई एम सॉरी। अभी जीरो आवर में यह चर्चा नहीं होगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, इस विषय पर मैं दो-तीन बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिला हूँ। मैंने होम मिनिस्टर से भी बात की है, लेकिन इन्होंने इसका जो असेसमेंट किया है उसके तहत ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष ः नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

12.16 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other

hon. Members left the House.)